पिट्स

आर.एन.आई. ३८१३९/८१

www.pits.co.in

वर्ष २९ अंक-२० सोमवार,५ जनवरी २००९ पृष्ठ १६ मूल्य दो रुपये

इंदौर-मुंबई से एक साथ प्रकाशित

पार्टी संगठन को कसने में जुटीं मायावती

बसपा प्रमुख मायावती अब संगठन को कसने में जुट गयी हैं। उन्होंने जिलों में पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी में इजाफा करने के साथ ही राज्य की हर लोकसभा सीट पर पूर्व में घोषित किये जा चुके प्रत्याशियों की परफार्मेंस की समीक्षा करने का कार्य शुरू किया है। बसपा प्रमुख ने आजमगढ़ से चुनाव जीते अकबर अहमद डम्पी का टिकट काट दिया है और पूर्व विधायक मलिक मसूद को आजमगढ़ सीट से प्रत्याशी बनाये जाने की जानकारी पार्टी पदाधिकारियों को दी। इसी तरह से सुल्तानपुर से पार्टी सांसद मो.ताहिर की जगह पप्पू रिजवान के चुनाव लड़ने और फैजाबाद से पार्टी सांसद मित्रसेन यादव के स्थान पर राजन मिश्र को पार्टी प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से सीएन सिंह की जगह अब शिव प्रकाश मिश्र, सम्भल से परमेश्वर सैनी, बिजनौर से शाहिद सिद्दीकी तथा नगीना से पूर्व आईएएस अधिकारी आरके सिंह को पार्टी प्रत्याशी बनाये जाने का एलान किया गया है।

चुनावी बयार राहतों की बौछार

चुनाव पूर्व 60 हजार करोड़ के राहत पैकेज और घोषित होंगे

देश में लोकसभा चुनाव की बयार बहना शुरू हो गई है और चुनाव में विजय के लिये पासे चले जाने लगे हैं. पिछले चार साल से गरीब के निवाले को नजर अंदाज कर रही केन्द्र सरकार की निगाह अब गरीब की थाली पर पड़ने लगी है और वह राहत की बौछार कर बेकाबू महंगाई को काबू में करने की जहां कोशिश कर रही है. वहीं उद्योगों और अर्थव्यवस्था को मंदी की मार से बचाने के लिये राहत की बौछारें कर रही है. इन सरकारी प्रयासों का असर बाजार में भी दिखाई दे रहा है. 20 हजार करोड़ के पहले राहत पैकेज ने महंगाई को जहां 13 से 8 फीसदी तक गिरा दिया है वहीं वर्ष की शुरूआत में दूसरे बड़े राहत पैकेज की घोषणा के बाद अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने और महंगाई के और घटने की उम्मीद बढ़ गई है.

वैश्विक मंदी से ठिठुरते बाजार के चलते भारतीय बाजार भी धराशायी हो रहे थे शेयर सूचकांक 21 हजार से औंधे मुंह गिरकर 9000 पर आ गया था इंफोसीस से लेकर तमाम कंपनियां मंदी की मार से बेजार हो गई थी तथा छंटनी एवं खर्च में कटौती के उपाय कर रही थी. 90 दिन बाद देश में लोकसभा के चुनाव होना है और चाहे सत्तारुढ़ यूपीए हो या विपक्षी एनडीए, सभी को देश के भाग्य विधाता मतदाता के पास जाना है सो चार साल तक महंगाई में पिस रही गरीब मध्यवर्गीय जनता का ख्याल अब हर राजनैतिक दल को होने लगा है और वह अपने -अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश करने लगा है. करीब 15 दिन पूर्व केन्द्र सरकार ने 20 हजार करोड़ के एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा की थी. जिसका व्यापक असर हुआ था. महंगाई को जहां ब्रेक लगा था वहीं बाजार में पूंजी संकट भी हल होता दिखाई दे रहा था. बाजार में सरलता बड़ी थी, बैंकों ने हाऊसिंग सहित सभी कर्ज की ब्याज दरें घराई थी. विश्वमंदी के चलते तेल बाजार 135 डालर से घटकर न्यूनतम 35 डालर प्रति बेरल पर पहुंच गया है जिससे तेल पूल घाटा खत्म होकर पेट्रोल-डीजल पर तेल कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही है. वर्तमान में पेट्रोल पर 12 रुपये एवं डीजल पर 4 रुपये से अधिक का मुनाफा हो रहा है. जिसके चलते इसी सप्ताह पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम क्रमशः 10 रुपये, 3 रुपये और 40 रुपये तक कम किये जाने की संभावना है.

कुल मिलाकर यह सारी कवायद चुनाव को देखते हुए की जा रही है. यूपीए के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और इस गठबंधन के सभी सहयोगी दलों का दबाव है कि महंगाई पर हर हाल में काबू किया जाना चाहिए. इसी के चलते ये प्रयास शुरू हुए हैं जिसका बाजार पर व्यापक असर दिखाई देने लगा है. लोकसभा के चुनाव अप्रैल अंत या मई में हर हाल में होंगे और रोजगार तथा महंगाई इस चुनाव में बड़े मुद्दे बनकर उभरने की संभावना है. ऐसे में यूपीए को भी इस बात का अहसास हो गया है कि यदि उसने महंगाई को काबू में नहीं किया तो उसका दोबारा सत्ता पर पहुंचना आसान नहीं होगा. इसी के चलते केन्द्र सरकार 40 हजार करोड़ के दो पैकेज तो घोषित कर चुकी है. आचार संहिता लागू होने से पहले 60 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा और संभावित है.

राहत के पैकेज

उत्तम झंवर

नए साल की शुरूआत के साथ ही देशभर में मंदी से उबरने के तोहफे सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। दो पैकेजों के जरिये राहत हर आम खास को मिल रही है। नवल नव लहर से गेहूं के निर्यात से प्रतिबंध हटा। साथ ही मुद्रास्फिति की दर में भी बढ़त हुई। रिर्जव बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देगा। साथ ही ब्याज की सुविधा भी रिवर्स रेपो दर से मिलेगी। बाजार की तरलता को घटाने-बढाने के लिए सीआरआर भी प्रावधान में है। रीयल एस्टेट कंपनियां भी विदेशी ऋण उठा सकगी। सेना के लिए नया वेतन आयोग है। चीफ जस्टिस व अन्य के वेतन में वृद्धि हुई। वहीं खास बात ये कि कालेज के मास्साब को भी आईएएस के बराबर तन्ख्वाह मिलेगी। द्रोण जैसी इज्जत न सही लेकिन सही वेतनमान उन्हें मास्साब से प्रोफेसर साहब बनने में भी मदद करेगा।

तुम्हारी-मेरी बातें चलती रहें.., इसके लिए ट्राई भी कोशिश कर रहा है कि बातों पर लगने वाले बेवजह के चार्ज को कम कर सके। उधर मुंबई के दर्द पर महरम लगाने की बात करें तो हर दिन उन्हें नाखूनों से और कचौटा जा रहा है। पाकिस्तान से मिलने वाले संदेशों के पुख्ता सबूत मिलने के बाद भी इस पर विशेष कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लोगों की सुनें तो इस पार या उस पार की लड़ाई के लिए लोग तैयार हैं। ई-मेल के जरिये लोग भारत के नए नक्शे को एकदूसरे को फारवर्ड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इसमें पाकिस्तान को शामिल कर विस्तृत भारत बनाया गया है। 2009 में इस नक्शे को पूर्ण स्वरूप दे देने में होने वाली किसी भी तरह की हानि के लिए अब लोग तैयार हैं। जरूरत है तो बस एक शुरूआत की।